अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए — लोक सभा अध्यक्ष

जेनेवा, 24 अक्तूबर 2016 : लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन जो इस समय जेनेवा में 135 वीं अंतर संसदीय संघ सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एक स्पष्ट नीति और प्रभावी रणनीति तैयार करके आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आह्वान किया।

इस बात पर जोर देते हुए कि वैश्वीकरण के युग में किसी एक देश की सफलता अथवा विफलता का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है, श्रीमती महाजन ने कहा कि सभी देशों को मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवाधिकारों के बहाने किसी संप्रभु राज्य के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए वक्तव्य पर उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू और काश्मीर राज्य से संबंधित अंदरूनी मामलों के बारे में पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां किए जाने के लिए अंतर संसदीय संघ के महत्वपूर्ण मंच का दुरूपयोग किए जाने की आलोचना की। पकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया कि सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न भाग है और हमेशा रहेगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कश्मीर में मौजूद स्थिति का मूल कारण पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमापार आतंकवाद है।

श्रीमती महाजन के नेतृत्व वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और पकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। बल्कि यह वैश्विक आतंकवाद का जनक है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध आतंकवादी और आतंकी समूह पकिस्तान में बेधड़क खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पकिस्तान की छद्म सरकार अंतरराष्ट्रीय सहायता के रूप में प्राप्त करोड़ों डॉलरों का उपयोग पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने के लिए कर रही है। यह भी कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में ही हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की ओर विश्व को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून्ख्वा के लोग पकिस्तान की सत्तावादी और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष, आतंकवाद और घोर आर्थिक गरीबी का शिकार बन रहे हैं जो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

तदनुसार, पाकिस्तान को सलाह दी गई कि वह स्वभावानुसार अन्यत्र मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामले उठाने की बजाय अपने देश में स्थितियां सुधारने और अपने पडोसी देशों में आतंकवादी हमले करवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करें। पकिस्तान को यह सुझाव भी दिया गया कि पहले वह पाक अधिकृत कश्मीर में अवैध कब्ज़ा हटवाने के संकल्प के अंतर्गत अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करें। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने पकिस्तान से भारत के किसी भी भाग में हिंसा भड़काने और आतंकवाद का समर्थन करने को रोकने और हमारे देश के किसी भी अंदरूनी मामले में दखलन्दाजी न करने का आह्वान भी किया ।

भारत की ओर से उत्तर लोक सभा सदस्य, श्री आर. के. सिंह ने दिया।